भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3756

जिसका उत्तर 25.03.2026 को दिया जाना है

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और हाई-स्पीड कॉरिडोर

3756 श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः
श्री केसरीदेवसिंह झालाः
श्री मिथलेश कुमारः
श्रीमती सीमा द्विवेदीः
श्री मयंककुमार नायकः
डा. मेधा विश्राम कुलकर्णीः
डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंहः
श्री उज्जवल देवराव निकमः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का पूरा निर्माण जून 2026 की संशोधित समय सीमा तक पूरा होने की राह पर है;

(ख) मई 2026 तक दिल्ली-वडोदरा खंड के पूरा होने से पांच राज्यों में वाणिज्यिक यात्रा का समय किस प्रकार कम हुआ है;

(ग) किन विशिष्ट भौगोलिक चुनौतियों के कारण गुजरात में शेष तीन परियोजनाओं में वर्ष 2027-28 वित्त वर्ष तक देरी हुई; और

(घ) हाल ही में भूमि अधिग्रहण और उपयोगिता स्थानांतरण संबंधी मुद्दों के समाधान के बाद संस्वीकृत बजट का कितना हिस्सा अप्रयुक्त बचा है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) सरकार ने भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का कार्यान्वयन शुरू किया है जो हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों से होकर गुजरता है, और मुंबई, महाराष्ट्र में समाप्त होता है। इस गलियारे के कार्यान्वयन में इसकी स्पर संपर्कता सहित 54 निर्माण पैकेज शामिल हैं, जिनकी कुल लंबाई 1,445 किमी है, जिनमें से 929 किमी चालू हो चुके हैं।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली-वडोदरा खंड में से 912 किलोमीटर में से 697 किलोमीटर चालू हो चुका है और 215 किलोमीटर कार्यान्वयन के अधीन है। दिल्ली-वडोदरा खंड को जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

गुजरात राज्य में वडोदरा-मुंबई खंड के पैकेज 8, 9 और 10 सहित गलियारे की निर्माण प्रगति मुख्य रूप से ठेकेदार की ओर से देरी के कारण प्रभावित हुई है। गुजरात राज्य में इन पैकेजों को मार्च, 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है जबकि अन्य पैकेज 2026 में पूरे हो जाएंगे।

(घ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सरकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ कार्यान्वयन एजेंसी के अनुसार निधि/ बजट आवंटित करती है, न कि परियोजना के अनुसार और विशेष रूप से निर्माण-पूर्व गतिविधियों के लिए। हालांकि, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की स्वीकृत लागत 96,547 करोड़ रुपये है, जबकि दिसंबर, 2025 तक 77,558 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

*****